आकाशवाणी केन्द्र शिमला

11.02.2026 / प्रादेशिक समाचार / 11:00बजे

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर राज्य के खजाने को विकास कार्यों और आवश्यक अधोसंरचना पर खर्च करने के बजाय फिजूलखर्ची और राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार को पांच वर्ष के कार्यकाल में 54 हजार 2 सौ 96 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) मिला था। इसके अलावा पूर्व भाजपा सरकार को 16,000 करोड़ रुपये की जीएसटी क्षतिपूर्ति भी मिली थी जिसका उपयोग राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने के बजाय मुफ्त योजनाओं और केंद्रीय नेतृत्व को खुश करने के लिए अनावश्यक कार्यक्रमों और संस्थानों को खोलने पर खर्च किया गया। उन्होंने कहा कि इसके मुकाबले वर्तमान सरकार को पिछले तीन वर्षों में केवल 17 हजार 5 सौ 63 करोड़ रुपये आरडीजी मिली है, जो भाजपा को मिली राशि से लगभग आधी है।

इस बीच मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व की भाजपा सरकार पर लगाए गए वित्तीय कुप्रबंधन के आरोपों को सिरे से नकारते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 16वें वित्तायोग मे राजस्व घाटा अनुदान को बंद करने का ऐलान अभी किया लेकिन तैयारी 15 वें वित्तायोग ही नहीं 12वे वित्तायोग के बाद आयोग बार–बार कह रहा है कि राजस्व अनुदान घाटे को अधिकार के रूप में नहीं लिया जा सकता। ये केंद्र की ओर से मदद है।

सूचना प्रौद्योगिकी

उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने कहा कि वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में लोगों और सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सुरक्षित उपयोग की जानकारी होना आवश्यक है और जिला किन्नौर सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यह अति आवश्यक है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण आवश्यक और संवेदनशील सूचनाओं का दुरुपयोग न हो सके। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डीपफेक जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सुरक्षित डिजिटल विकल्पों का चुनाव करना, साइबर हाइजीन, आम जनता को अपने पासवर्ड की सुरक्षा और संदिग्ध लिंक्स से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया है। अमित कुमार ने कहा कि डिजिटल साक्षरता के मध्यम से युवाओं और छात्रों को ऑनलाइन जानकारी की सत्यता परखने और व्यक्तिगत डाटा को सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित करना बेहद जरूरी है।

जल शक्ति विभाग

जल शक्ति विभाग धर्मशाला जोन ने गर्मियों से पहले नौ बड़ी योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। हालांकि कुछ छोटी योजनाएं भी हैं, जिन पर कार्य चल रहा है, लेकिन बड़ी योजनाओं

के कार्य को विभाग युद्ध स्तर पर परा कर रहा है, जिससे कि गर्मियों तक इन योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सके। जल शक्ति विभाग धर्मशाला जोन के मुख्य अभियंता दीपक गर्ग ने बताया कि जयसिंहपुर क्षेत्र के लिए दो बड़ी योजनाओं पर करीब 100 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं, जिन्हें आगामी एक–दो महीने के भीतर जनता को समर्पित कर दिया जाएगा।

दिशानिर्देश

नगर व ग्राम नियोजन विभाग ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने और जनसमस्याओं का समयबद्ध निवारण करने के उद्देश्य से शिकायत निवारण प्रणाली के तहत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत नगर व ग्राम नियोजन विभाग में तीन स्तरीय शिकायत निवारण व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत डिविजिनल जिला और राज्य स्तर पर शिकायतों की सुनवाई और समाधान की प्रक्रिया तय की गई है। विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि चंबा, ऊना और बिलासपुर ज़िलों में डिविजनल टाउन प्लानिंग कार्यालय न होने की स्थिति में चंबा के लोग धर्मशाला, ऊना के हमीरपुर और बिलासपुर ज़िला के लोग टाउन एंड कंट्री प्लानर मंडी को अपनी शिकायतें प्रेषित कर सकते हैं।